ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 4, July 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

भारत -संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध: मोदी सरकार में 2014 के बाद

Gaurav Choudhary

Assistant Professor, Political Science, Government College, Jahazpur, Bhilwara, Rajasthan, India

सार

11 जून 2014 को, रॉबर्ट ब्लैकविलजॉर्ज डब्ल्यू बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान रणनीतिक योजना के पूर्व समन्वयक और उप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ने भारत-अमेरिका संबंधों के बारे में विस्तार से बात की और कहा: "श्री मोदी एक दृढ़ नेता हैं। वह स्पष्टवादी और स्पष्टवादी हैं। मैंने भी काम किया है।" गुजरात भूकंप के दौरान उनके साथ था जब मैं भारत में (अमेरिकी) राजदूत के रूप में तैनात था। ... श्री मोदी के साथ बातचीत में देरी करना वर्तमान ओबामा प्रशासन की गलती थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया लेकिन निश्चित रूप से, ऐसा हुआ था संबंध बनाने में मदद नहीं। ... यदि अमेरिकी प्रशासन श्री मोदी के साथ जुड़ना चाहता है तो पुराने फॉर्मूले और रूढ़िवादिता काम नहीं करेगी। भारतीय प्रधान मंत्री स्पष्टवादी, प्रत्यक्ष और चतुर हैं। वह अपने मन की बात कहते हैं। अमेरिकी प्रशासन को भी ऐसा करना होगा जब श्री मोदी इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति ओबामा से मिलेंगे तो स्पष्ट बातचीत में शामिल हों।उनसे जुड़ने के लिए उन्हें कुछ नया करना होगा।

परिचय

2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। [164] वर्तमान में, भारत और अमेरिका एक व्यापक और विस्तारित सांस्कृतिक, रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंध साझा करते हैं [165] [166] [167] जो प्रतिकूल अमेरिकी विदेश नीतियों [168] [169] और प्रौद्योगिकी इनकार के कई उदाहरणों [170] [171] [172] विश्वास की कमी की विरासत को दूर करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) को लागू करने के चरण में है - जिसने कई दशकों से संबंधों को प्रभावित किया है। [173]2008 के अमेरिका-भारत नागरिक परमाणु समझौते के समापन के बाद अवास्तविक उम्मीदें , जिसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और सुरक्षा उपायों और दायित्व पर संविदात्मक गारंटी के लिए नागरिक-समाज के समर्थन के बारे में नकारात्मक जनता की राय को कम करके आंका, ने व्यावहारिक यथार्थवाद का मार्ग प्रशस्त किया है और सहयोग के उन क्षेत्रों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें जिनमें अनुकूल राजनीतिक और चुनावी सहमति है।

हाल के प्रमुख घटनाक्रमों में भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, भारतीय और अमेरिकी उद्योगों के बीच विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध, तेजी से मुखर हो रहे चीन को प्रबंधित करने के लिए एक अनौपचारिक समझौता, जवाबी कार्रवाई पर मजबूत सहयोग शामिल हैं । आतंकवाद, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में गिरावट , दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण में ढील (आवेदन किए गए 99% लाइसेंस अब स्वीकृत हैं), [[174] और भारत के रणनीतिक कार्यक्रम के लिए लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी विरोध को उलट दिया गया है।

अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, एशियाई भारतीयों द्वारा ज्ञान-आधारित रोजगार के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में आय सृजन ने अन्य सभी जातीय समूहों को पीछे छोड़ दिया है। [175] समृद्ध एशियाई भारतीय प्रवासियों का बढ़ता वित्तीय और राजनीतिक दबदबा उल्लेखनीय है। 100,000 अमेरिकी डॉलर के औसत राजस्व के साथ भारतीय अमेरिकी परिवार अमेरिका में सबसे समृद्ध हैं और इसके बाद 65,000 अमेरिकी डॉलर के साथ चीनी अमेरिकी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत घरेलू राजस्व 63,000 अमेरिकी डॉलर है। [176]

व्यापार से लेकर नागरिक स्वतंत्रता तक के मुद्दों पर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद जारी है। भारतीय गृह मंत्रालय ने 13 फरवरी 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे के माध्यम से दावा किया कि अधिकारों और प्रथाओं पर देश की रिपोर्ट विदेश नीति का साधन बन गई है: "अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने सरकारी दस्तावेजों और घोषणाओं में स्पष्ट

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

रूप से उल्लेख किया है कि ये रिपोर्टें विदेश नीति के उपकरणों के रूप में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।" हलफनामे में यह भी दावा किया गया कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संसद की रिपोर्टें पक्षपातपूर्ण थीं क्योंकि वे "भारत सरकार या स्थानीय दूतावास/उच्चायोग को अपनी राय दर्ज करने का अवसर प्रदान नहीं करती हैं और लक्षित देश के खिलाफ भारी पक्षपातपूर्ण हैं"। [177] 2014 विदेश विभाग का वार्षिकमानव तस्करी (टीआईपी) रिपोर्ट में खोबरागड़े घटना को मानव तस्करी के एक उदाहरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कहा गया है: "न्यूयॉर्क वाणिज्य दूतावास में एक भारतीय कांसुलर अधिकारी को दिसंबर 2013 में एक भारतीय घरेलू कामगार के कथित शोषण से संबंधित वीजा धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया था। ।" [178] जवाब में, भारत ने नवनियुक्त अमेरिकी मानव तस्करी विरोधी राजदूत सुसान पी. कॉपेज और एलजीबीटी अधिकारों के लिए अमेरिकी विशेष दूत रैंडी बेरी की भारत यात्रा की अनुमति देने में कोई तत्परता नहीं दिखाई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहतभारत में समलैंगिकता गैरकानूनी थी. अमेरिका में भारतीय राजदूत, अरुण के. सिंह ने तस्करी की समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय ढांचे के भीतर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन किसी अन्य देश के "एकतरफा आकलन" को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे" और यात्राओं के महत्व को कम कर दिया। : "जब आप किसी अमेरिकी अधिकारी से पूछते हैं कि किसी को वीज़ा कब दिया जाएगा, तो वे हमेशा कहते हैं 'जब वीज़ा के लिए आवेदन किया जाएगा तो हम इसका आकलन करेंगे।' ...मैं अमेरिकी स्थिति को दोहराने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता।" [179]

फरवरी 2016 में, ओबामा प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि वह पाकिस्तान को आठ परमाणु-सक्षम F-16 लड़ाकू विमान और आठ AN/APG-68 (V)9 हवाई रडार और आठ ALQ-211(V) सहित मिश्रित सैन्य सामान प्रदान करना चाहता है। 9 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट्स [180] [181] पाकिस्तान को किसी भी परमाणु हथियार सक्षम प्लेटफॉर्म के हस्तांतरण के संबंध में अमेरिकी सांसदों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद। [182]भारत में कांग्रेस पार्टी के एक निर्वाचित प्रतिनिधि, शशि थरूर ने भारत-अमेरिका संबंधों के सार पर सवाल उठाया: "मैं यह खबर सुनकर बहुत निराश हूं। सच्चाई यह है कि एक गैर-जिम्मेदार शासन के लिए उपलब्ध हथियारों की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है।" भारत में आतंकवादियों को भेजा और आतंकवाद-विरोध के नाम पर यह सर्वोच्च स्तर की निराशा है।" [183] भारत सरकार ने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के संबंध में अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए भारत में अमेरिकी राजदूत को बुलाया।

राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत संबंध (2017-2021)

अगस्त 2019 में फ्रांस के बिआरिट्ज़ में 45वें G7 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी

फरवरी 2017 में, अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सरना ने नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन (एनजीए) के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी की , जिसमें 25 राज्यों के राज्यपाल और 3 और राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पहली बार था जब ऐसी घटना घटी। सभा का कारण बताते हुए, वर्जीनिया के गवर्नर और एनजीए अध्यक्ष टेरी मैकऑलिफकहा कि "भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है"। उन्होंने आगे कहा, "हम भारत के, भारत-अमेरिका संबंधों के रणनीतिक महत्व को स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे-जैसे हम अपनी 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था विकसित कर रहे हैं, भारत हमारी प्रौद्योगिकी, चिकित्सा व्यवसायों के निर्माण में मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हम एक ऐसे देश को पहचानते हैं जो ऐसा रहा है।" अमेरिका का इतना करीबी रणनीतिक सहयोगी। यही कारण है कि हम गवर्नर आज रात यहां हैं।" 15 बार भारत का दौरा कर चुके मैकऑलिफ ने अन्य गवर्नरों से भी अवसरों का लाभ उठाने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के साथ देश का दौरा करने का आग्रह किया। [185]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

अक्टूबर 2018 में, भारत ने अमेरिका के CAATSA अधिनियम की अनदेखी करते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक, चार S-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक समझौता किया । रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। [186] ईरान से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी । [187]यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष मुकेश अघी के अनुसार, "प्रतिबंधों का आने वाले दशकों में अमेरिका-भारत संबंधों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। भारत की नजर में, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बार फिर अविश्वसनीय माना जाएगा।" ।" [188] ट्रम्प प्रशासन ने रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली के लिए भारत को मंजूरी देने से परहेज किया, लेकिन उसी खरीद के लिए तुर्की और चीन को मंजूरी दे दी। [189]

राष्ट्रपति ट्रम्प भारत की भाजपा सरकार के करीब आ गए हैं , जो समान दक्षिणपंथी विचारों को साझा करती है, उन्होंने बार-बार मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है और नागरिकता और कश्मीर विवादों पर भारत सरकार के कार्यों की किसी भी नकारात्मक आलोचना से परहेज किया है। [190] [191] ट्रम्प प्रशासन " कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद " से निपटने में मोदी प्रशासन के साथ सुसंगत है , [192] और अमेरिका भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को खत्म करने के लिए अपना समर्थन दोहराता है । [193] [194]

2020 की शुरुआत में, भारत ने चल रहे कोरोनोवायरस (सीओवीआईडी -19) महामारी के खिलाफ लड़ाई के बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक एक औषधीय दवा पर निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अपना समझौता प्रदान किया , जब ट्रम्प ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, अगर उसने निर्यात को समाप्त करने का अनुपालन नहीं किया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर प्रतिबंध। [195] [196]

जून 2020 में, जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध प्रदर्शन के दौरान , 2 और 3 जून की मध्यरात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा वाशिंगटन, डीसी में महात्मा गांधी स्मारक में तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना ने भारतीय दूतावास को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने बर्बरता को "मानवता के खिलाफ अपराध" कहा। [197] [198] अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने को "अपमानजनक" बताया। [199]

21 दिसंबर 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-संयुक्त राज्य संबंधों को ऊपर उठाने के लिए मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। लीजन ऑफ मेरिट से मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आबे के साथ सम्मानित किया गया , जो क्वाड के "मूल वास्तुकार" थे । [200] [201]

मोदी-बिडेन संबंध (2021 से आगे)

अप्रैल 2021 में अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव शुरू हो गया जब भारत को COVID-19 संक्रमण में बड़े पैमाने पर वृद्धि का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने घरेलू वैक्सीन उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए टीके के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1950 के रक्षा उत्पादन अधिनियम को लागू किया था। [202] टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार , इससे भारत में अमेरिका विरोधी भावना का भी विस्फोट हुआ, क्योंकि अमेरिका के पास वैक्सीन भंडार था और उसने COVID-19 वैक्सीन पेटेंट साझा करने से इनकार कर दिया। [203] यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला की याचिका के बाद आया, COVID-19 टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। [196] हालांकि, अप्रैल के अंत में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक फोन कॉल के ठीक बाद , बिडेन प्रशासन ने कहा कि वह ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका सीओवीआईडी -19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत को उपलब्ध कराएगा। और ₹ 714 करोड़ (2023 में ₹ 798 करोड़ या यूएस $ 100 मिलियन के बराबर) से अधिक मूल्य की दवा उपचार, रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण , वेंटिलेटर , व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भेजना शुरू किया।, और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम के साथ, भारत में टीके बनाने के लिए आवश्यक यांत्रिक हिस्से । अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने भारतीय स्थित COVID-19 वैक्सीन उत्पादन कंपनी बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड के विस्तार को वित्तपोषित करने की योजना बनाई है। भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में प्रवेश किया जब उसने घोषणा की कि वह दुनिया के साथ 60 मिलियन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीके साझा करेगा। [208]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

यूएसएस जॉन पॉल जोन्स घुसपैठ

यूएसएस जॉन पॉल जोन्स नवंबर 2002 में कैलिफोर्निया के तट से दूर

7 अप्रैल, 2021 को, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, नई दिल्ली की पूर्व सहमति के बिना, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर गुजरे, फिर सार्वजनिक रूप से इस कार्यक्रम की घोषणा की, जिससे राजनयिक विवाद पैदा हो गया। [209] [210] ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत संबंधों को गहरा कर रहे थे, इस तरह के कदम ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में आम जनता के बीच नाराजगी पैदा कर दी थी । संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े के आधिकारिक बयान के अनुसार , "7 अप्रैल, 2021 (स्थानीय समय) पर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स (डीडीजी 53) ने भारत के अंदर, लक्षद्वीप द्वीप समूह के पश्चिम में लगभग 130 समुद्री मील की दूरी पर नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का दावा किया।विशेष आर्थिक क्षेत्र , भारत की पूर्व सहमति के अनुरोध के बिना, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है । "भारत को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ में सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता है , यह दावा अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ असंगत है। नेविगेशन ऑपरेशन की यह स्वतंत्रता ("एफओएनओपी")) ने भारत के अत्यधिक समुद्री दावों को चुनौती देकर अंतरराष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त समुद्र के अधिकारों, स्वतंत्रता और वैध उपयोग को बरकरार रखा। बयान में आगे कहा गया, "अमेरिकी सेना दैनिक आधार पर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में काम करती है । सभी ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून अनुमति देगा वहां उड़ान भरेगा, जलयात्रा करेगा और संचालन करेगा। पेंटागन ने यह दावा करते हुए 7वें बेड़े के बयान का बचाव किया कि यह घटना अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप थी। [210]

भारतीय विदेश मंत्रालय ने काफी मीडिया के ध्यान के बाद अपना बयान जारी किया, बयान में कहा गया, "समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर भारत सरकार की घोषित स्थिति यह है कि कन्वेंशन अन्य राज्यों को इसमें शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं करता है।" विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ पर, तटीय राज्य की सहमति के बिना, सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास, विशेष रूप से हथियारों या विस्फोटकों के उपयोग से संबंधित", इसमें आगे कहा गया है, "यूएसएस जॉन पॉल जोन्स की लगातार निगरानी की जा रही थी। मलक्का जलडमरूमध्य की ओर फारस की खाड़ी । हमने अपने ईईजेड के माध्यम से इस मार्ग के संबंध में राजनयिक चैनलों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है।" [209] [212] भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने ट्वीट कर इस घटना पर टिप्पणी की, "यहां विडंबना है। जबकि भारत ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून की पुष्टि की थी , अमेरिका अब तक ऐसा करने में विफल रहा है। 7वें बेड़े के लिए हमारे घरेलू कानून का उल्लंघन करके भारतीय ईईजेड में FoN मिशन को अंजाम देना काफी बुरा है। लेकिन इसे प्रचारित करना? यूएसएन कृपया आईएफएफ पर स्विच करें ! "। उन्होंने आगे ट्वीट किया, ' दक्षिण चीन सागर में यूएसएन जहाजों द्वारा FoN ऑपरेशन (जैसा कि वे अप्रभावी हो सकते हैं) चीन को एक संदेश देने के लिए हैं।कृत्रिम एससीएस द्वीपों के आसपास कथित ईईजेड एक 'अत्यधिक समुद्री दावा' है। लेकिन भारत के लिए 7वें बेड़े का संदेश क्या है?" [213] [214]

विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करें

हालाँकि यूक्रेन में युद्ध को लेकर कुछ मतभेद हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने जो बिडेन के राष्ट्रपति पद के दौरान रक्षा, अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है । [215] बिडेन ने भारत के साथ संबंधों को "21वीं सदी के निर्णायक रिश्तों में से एक" भी कहा। [216] मोदी और बिडेन ने अल-कायदा, आईएसआईएस (दाएश), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में पहचाने गए सभी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान दोहराया।) और हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन (HuM)। साथ ही कहा कि अफगान तालिबान सरकार और पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना चाहिए। [217] [218]संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया, [219]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

"मानव उद्यम का कोई भी कोना हमारे दो महान देशों के बीच साझेदारी से अछूता नहीं है, जो समुद्र से लेकर सितारों तक फैला हुआ है।"

विचार-विमर्श

सैन्य संबंध

अमेरिका के चार "बुनियादी" समझौते हैं जिन पर वह अपने रक्षा साझेदारों के साथ हस्ताक्षर करता है। पेंटागन ने समझौतों को "नियमित उपकरण" के रूप में वर्णित किया है जिसका उपयोग अमेरिका साझेदार-राष्ट्रों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समझौते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए पूर्व शर्त नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के देशों में विमान या जहाजों को ईंधन भरने और आपदा राहत प्रदान करने जैसी गतिविधियों को आसान और अधिक लागत प्रभावी बना देंगे। [220]चार समझौतों में से पहला, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (जीएसओएमआईए), 2002 में भारत और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है और प्रत्येक देश को दूसरों की वर्गीकृत जानकारी की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। जानकारी।

दूसरा समझौता, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), 29 अगस्त 2016 को दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। LEMOA किसी भी देश की सेना को पुनः आपूर्ति या मरम्मत के लिए दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह समझौता साजो-सामान संबंधी सहायता के प्रावधान को किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं बनाता है और प्रत्येक अनुरोध के लिए व्यक्तिगत मंजूरी की आवश्यकता होती है। [221] तीसरे समझौते, संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर सितंबर 2018 में उद्घाटन 2+2 संवाद के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। [222]यह संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन (CISMOA) का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है जो दोनों देशों को द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास और संचालन के दौरान अनुमोदित उपकरणों पर सुरक्षित संचार साझा करने और जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। चौथा समझौता, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बीईसीए), 2020 में हस्ताक्षरित, भारत और यूएस नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच अवर्गीकृत और नियंत्रित अवर्गीकृत भू-स्थानिक उत्पादों, स्थलाकृतिक, समुद्री और वैमानिक डेटा, उत्पादों और सेवाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देता है । (एनजीए)। [223]

किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष वी. पंत ने अमेरिकी रणनीतिक योजना में भारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा: "भारत बड़े इंडो-पैसिफिक में शक्ति का एक स्थिर संतुलन बनाने की अमेरिका की क्षमता की कुंजी है।" संसाधनों की कमी के इस समय में, चीनी हमले के सामने क्षेत्र में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए इसे भारत जैसे साझेदारों की आवश्यकता है।'' नियर ईस्ट साउथ एशिया सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में साउथ एशिया स्टडीज के प्रोफेसर रॉबर्ट बोग्स का मानना है कि अमेरिका "संबंध सुधारने की भारत की इच्छा और ऐसा करने से होने वाले लाभ दोनों को अधिक महत्व देता है"। [224]

चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की नीतियों के हिस्से के रूप में, [225] ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में से एक भारत को प्रमुख रक्षा साझेदारों में से एक बनाना है जिसके लिए वह अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत शिकारी ड्रोन बेचने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है। [226] भारत ने नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय एमआरसीए प्रतियोगिता (जिसे सभी रक्षा सौदों की जननी भी कहा जाता है) में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 100 मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए निविदा जारी की है। हालाँकि 2018 में इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने उन्नत F-16 जेट लड़ाकू विमानों , [227] और F/A-18 सुपर हॉर्नेट की बिक्री पर जोर दिया ।[228]

भारतीय सेना और अमेरिकी सेना 2002 से युद्ध अभ्यास नामक एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करती है। 2022 में, यह अभ्यास उत्तराखंड में आयोजित किया गया था । [229]

जून 2015 में, अमेरिकी रक्षा सचिव एश्टन कार्टर ने भारत का दौरा किया और भारतीय सैन्य कमान का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी रक्षा सचिव बने। उसी वर्ष दिसंबर में, मनोहर पर्रिकर अमेरिकी प्रशांत कमान का दौरा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बने । [230]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

मार्च 2016 में, भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक गश्त में शामिल होने के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, "भारत ने कभी भी संयुक्त गश्त में हिस्सा नहीं लिया है; हम केवल संयुक्त अभ्यास करते हैं। संयुक्त गश्त का सवाल ही नहीं उठता।" [231]

जनवरी 2017 में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशियाई मामलों के वरिष्ठ निदेशक, पीटर लैवॉय ने घोषणा की कि बराक ओबामा के प्रशासन के तहत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी "अविश्वसनीय रूप से सफल" रही है। लैवॉय ने कहा, "मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि हमारी साझेदारी के कारण कई आतंकवादी साजिशों को नाकाम कर दिया गया। इस साझेदारी के कारण भारतीय और अमेरिकी लोगों की जान बचाई गई।" [232] [233]

27 अक्टूबर, 2020 को, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए अधिक जानकारी-साझाकरण और आगे रक्षा सहयोग संभव हो सके। [234] 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के दौरान संवेदनशील जानकारी साझा करने और उन्नत सैन्य हार्डवेयर की बिक्री के लिए चार तथाकथित "बुनियादी समझौतों" का अंतिम समझौता हुआ। [235]

16 अगस्त, 2022 को, अमेरिकी वायु सेना सचिव फ्रैंक केंडल ने कहा कि भारतीय रक्षा अताशे की अब पेंटागन तक बिना सुरक्षा पहुंच है और उन्होंने यह भी कहा कि यह एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति के साथ हमारे करीबी रिश्ते की शुरुआत है," और फ्यूचर ने कहा कि "और अगर आपको नहीं लगता कि पेंटागन में बिना सुरक्षा प्रवेश कोई बड़ी बात है, तो मैं बिना एस्कॉर्ट के पेंटागन में नहीं जा सकता।" [236]

2023 में मोदी की यात्रा के दौरान, अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हुए कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स संयुक्त रूप से GE F-414 जेट इंजन का उत्पादन करेगा । [237] दोनों पक्ष एमक्यू-9बी ड्रोन खरीदने के लिए भी एक समझौते पर पहुंचे। [215]

परमाणु सहयोग

पोखरण परीक्षण

1998 में, भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जिसके परिणामस्वरूप भारत पर कई अमेरिकी, जापानी और यूरोपीय प्रतिबंध लगे। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री, जॉर्ज फर्नांडीस ने कहा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम आवश्यक था क्योंकि यह संभावित परमाणु खतरों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। भारत पर लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध 2001 तक हटा दिए गए थे। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पहले कभी भी हथियारों का उपयोग नहीं करेगा लेकिन हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करेगा।

मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, कम से कम शुरुआत में, भारत-अमेरिका संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते प्रतीत हुए। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1994 के परमाणु प्रसार रोकथाम अधिनियम के अनुसार व्यापक प्रतिबंध लगाए । परमाणु उद्योग में शामिल भारतीय संस्थाओं पर अमेरिकी प्रतिबंध और भारत में गैर-मानवीय सहायता परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऋण का विरोध। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया(सीटीबीटी) तुरंत और बिना किसी शर्त के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से मिसाइल और परमाणु परीक्षण और तैनाती पर संयम बरतने का भी आह्वान किया। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद शुरू की गई अप्रसार वार्ता ने देशों के बीच समझ की कई कमियों को पाट दिया है।

तनाव कम होना

सितंबर 2001 के अंत में, राष्ट्रपति बुश ने मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद 1994 के परमाणु प्रसार रोकथाम अधिनियम की शर्तों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया। अप्रसार वार्ताओं के सिलसिले ने देशों के बीच समझ में कई अंतरों को पाट दिया।

दिसंबर 2006 में, अमेरिकी कांग्रेस ने ऐतिहासिक भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता|हेनरी जे. हाइड यूएस-भारत शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग अधिनियम पारित किया, जो 30 वर्षों में पहली बार भारत के साथ सीधे नागरिक परमाणु व्यापार की अनुमति देता है। अमेरिकी नीति पिछले वर्षों में भारत के साथ परमाणु सहयोग के विरोध में थी क्योंकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के खिलाफ परमाणु हथियार विकसित किए थे, और परमाणु अप्रसार संधि (एनएनपीटी) पर कभी हस्ताक्षर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

नहीं किए थे। यह कानून भारत के लिए अमेरिकी परमाणु रिएक्टर और नागरिक उपयोग के लिए ईंधन खरीदने का रास्ता साफ करता है।

भारत -संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को "123 समझौते" के रूप में भी जाना जाता है, जिस पर 10 अक्टूबर 2008 को हस्ताक्षर किया गया था, यह शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय समझौता है जो एक दूसरे के नागरिक परमाणु में भाग लेने के लिए अमेरिकी और भारतीय फर्मों के बीच नागरिक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है। ऊर्जा क्षेत्र। [238] [239] समझौते को क्रियान्वित करने के लिए, परमाणु विक्रेताओं और ऑपरेटरों को भारत के 2010 के परमाणु दायित्व अधिनियम का पालन करना होगा जो यह निर्धारित करता है कि परमाणु आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और ऑपरेटरों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय जिम्मेदारी वहन करनी होगी।

प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं (1984 भोपाल रासायनिक-गैस आपदा और 2011 फुकुशिमा परमाणु आपदा) ने नागरिक समाज द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विक्रेताओं और ऑपरेटरों की कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और वित्तीय दायित्व दायित्वों की अधिक जांच की है। 2010 में, भारतीय संसद ने चिंताओं को दूर करने और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व प्रदान करने और परमाणु घटना के पीड़ितों को त्वरित मुआवजा प्रदान करने के लिए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को पारित करने के लिए मतदान किया।

27 मार्च, 2019 को, भारत और अमेरिका ने भारत में छह अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों के निर्माण सहित "द्विपक्षीय सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग को मजबूत करने" के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। [240]

परिणाम

पोस्ट-11 सितंबर

आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में भारत के योगदान से कई देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों में मदद मिली है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका-भारत और यूरोपीय संघ-भारत द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। पिछले पांच वर्षों में यूरोप और अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना से अधिक हो गया है।

हालाँकि, भारत ने CTBT , या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है , इस संधि की भेदभावपूर्ण प्रकृति का दावा करते हुए, जो दुनिया के पांच घोषित परमाणु देशों को अपने परमाणु शस्त्रागार रखने और कंप्यूटर सिमुलेशन परीक्षण का उपयोग करके इसे विकसित करने की अनुमति देता है। अपने परमाणु परीक्षण से पहले, भारत ने दुनिया के सभी देशों द्वारा समयबद्ध सीमा में परमाणु हथियारों को व्यापक रूप से नष्ट करने पर जोर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने इसका समर्थन नहीं किया। वर्तमान में, भारत ने "परमाणु हथियारों का पहले उपयोग न करने" और "विश्वसनीय परमाणु निरोध" बनाए रखने की अपनी नीति घोषित की है। संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश के अधीनने भारत पर से अपने अधिकांश प्रतिबंध भी हटा लिए हैं और सैन्य सहयोग फिर से शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ है, दोनों देशों ने भारत के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त हवाई अभ्यास में भाग लिया है। [241] [242] [243]

भारत संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में सुधारों पर जोर दे रहा है जिसके मिले-जुले परिणाम आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को वर्तमान में रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राजील, अफ्रीकी संघ देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन प्राप्त है। 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, भले ही भारत परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं है । संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात पर सहमत हुआ कि भारत के मजबूत परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड ने इसे अपवाद बना दिया और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्यों को भारत के साथ इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया।

2 मार्च 2006 को, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागरिक परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर हस्ताक्षर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान किये गये। अपनी ओर से, भारत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करेगा, और नागरिक कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा उपायों के तहत लाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम की स्थापना और उन्नयन के लिए रिएक्टर तकनीक और परमाणु ईंधन बेचेगा। अमेरिकी कांग्रेस को

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

इस समझौते की पुष्टि करने की आवश्यकता है क्योंकि अमेरिकी संघीय कानून परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के ढांचे के बाहर परमाणु प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के व्यापार पर रोक लगाता है।

आर्थिक संबंध

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष निवेशकों में से एक है। 1991 से 2004 तक, एफडीआई प्रवाह का स्टॉक 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 344.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कुल 4.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह सालाना 57.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर वृद्धि है। विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश 1992 में शुरू हुआ, और भारतीय निगम और पंजीकृत साझेदारी फर्म अब अपने निवल मूल्य के 100 प्रतिशत तक व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं और करते हैं। भारत का सबसे बड़ा आउटगोइंग निवेश विनिर्माण क्षेत्र में है, जो देश के विदेशी निवेश का 54.8 प्रतिशत है। दूसरा सबसे बड़ा निवेश गैर-वित्तीय सेवाओं (सॉफ्टवेयर विकास) में है, जिसका योगदान 35.4 प्रतिशत है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर को पार कर गया।[244]

व्यापार संबंध

मार्च 2006 में नई दिल्ली में भारतीय और अमेरिकी व्यापारिक नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन

सिंह अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के अधिकारी 2015 में खाद्य सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन की समीक्षा करते हैं

2021 से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, [244] और भारत इसका 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है । [245] 2017 में, अमेरिका ने भारत को 25.7 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया, और 48.6 अरब डॉलर मूल्य का भारतीय सामान आयात किया। [246] भारत से आयातित प्रमुख वस्तुओं में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, कपड़ा , मशीनरी , रत्न और हीरे , रसायन , लौह और इस्पात उत्पाद, कॉफी , चाय शामिल हैं।, और अन्य खाद्य खाद्य उत्पाद। भारत द्वारा आयातित प्रमुख अमेरिकी वस्तुओं में विमान , उर्वरक , कंप्यूटर हार्डवेयर , स्क्रैप धातु और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। [247] [248]

10 बिलियन डॉलर (कुल विदेशी निवेश का 9 प्रतिशत) के प्रत्यक्ष निवेश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निवेश भागीदार भी है। अमेरिकियों ने एशियाई देश की बिजली उत्पादन, दूरसंचार, बंदरगाहों, सड़कों, पेट्रोलियम अन्वेषण और प्रसंस्करण, और खनन उद्योगों में उल्लेखनीय विदेशी निवेश किया है। [248]

2015 में भारत से अमेरिकी आयात $46.6 बिलियन या उसके कुल आयात का 2% था, और भारत के कुल निर्यात का 15.3% था। भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं [249] [250]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

रत्न , कीमती धातुएँ और सिक्के , फार्मास्यूटिकल्स , तेल , मशीनरी , कपड़ा (बुनाई और क्रोकेट सहित), कार्बनिक रसायन , वाहन , और लौह या इस्पात उत्पाद

2015 में भारत को अमेरिकी निर्यात $20.5 बिलियन या भारत के कुल आयात का 5.2% था। अमेरिका से भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं: [251] [252] रत्न , कीमती धातुएँ और सिक्के, मशीनरी , इलेक्ट्रॉनिक उपकरण , चिकित्सा उपकरण, तेल , विमान/अंतरिक्ष यान, प्लास्टिक , कार्बनिक रसायन , फल और मेवे ।

जुलाई 2005 में, राष्ट्रपति बुश और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने व्यापार नीति फोरम नामक एक नया कार्यक्रम बनाया। [253] इसे प्रत्येक राष्ट्र के एक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉब पोर्टमैन थे , और भारतीय वाणिज्य सचिव तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमल नाथ थे. कार्यक्रम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। व्यापार नीति फोरम के पांच मुख्य उप-विभाग हैं, जिनमें कृषि व्यापार समूह भी शामिल है, जिसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं: उन शर्तों पर सहमत होना जो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका में आम निर्यात करने की अनुमति देगा, भारत के कृषि और प्रक्रिया खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को अनुमति देगा। (एपीडा) भारतीय उत्पादों को अमेरिकी कृषि विभाग के मानकों के अनुरूप प्रमाणित करना और फलों पर खाद्य मोम को मंजूरी देने के लिए विनियमन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना।

टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधा समूह के लक्ष्यों में इस बात पर सहमति शामिल है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा निर्मित कीटनाशक पूरे भारत में बेचे जा सकते हैं। भारत कार्बोनेटेड पेय , कई औषधीय दवाओं के व्यापार पर विशेष नियमों में कटौती करने और कई आयातों पर नियमों को कम करने पर भी सहमत हुआ था जो कृषि प्रकृति के नहीं हैं। दोनों देश आभूषण , कंप्यूटर पार्ट्स , मोटरसाइकिल , उर्वरक के व्यापार में भारतीय विनियमन के बेहतर पहलुओं और उन टैरिफों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं जो बोरिक एसिड के अमेरिकी निर्यात को प्रभावित करते हैं । समूह ने लेखांकन बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों जैसे मामलों पर भी चर्चा की है।भारतीय कंपनियाँ दूरसंचार उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त कर रही हैं , और भारतीय मीडिया और प्रसारण बाजारों के संबंध में नीतियां निर्धारित कर रही हैं। अन्य फोकस में विभिन्न पेशेवर सेवाओं को पहचानने, विकासशील उद्योगों में लोगों की आवाजाही और स्थिति पर चर्चा, वित्तीय सेवा बाजारों पर बातचीत जारी रखने, इक्विटी की सीमा, बीमा, खुदरा, कृषि प्रसंस्करण और परिवहन उद्योगों में संयुक्त निवेश पर बहुमूल्य जानकारी का आदान-प्रदान शामिल है। और लघु व्यवसाय पहल।

3 अगस्त, 2018 को, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण-1 (STA-1) का दर्जा पाने वाला तीसरा एशियाई राष्ट्र बन गया। STA-1 अमेरिका से भारत में नागरिक अंतरिक्ष और रक्षा में उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाता है। [254] [255]

15 फरवरी, 2023 को एयर इंडिया ने 470 जेट के ऑर्डर की घोषणा की, जिसमें से 220 जेट बोइंग से और अन्य 250 एयरबस से खरीदे जाएंगे। यह वाणिज्यिक जेट उद्योग में सबसे बड़े विमान ऑर्डरों में से एक है। इस सौदे को POTUS और भारत के PMO दोनों ने स्वीकार किया था। [256]

2023 में मोदी की यात्रा के दौरान, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान, बाजार पहुंच के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच सात बकाया डब्ल्यूटीओ विवादों में से छह का समाधान। [215]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

31 जनवरी, 2023 को यूएस-इंडिया सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की आठवीं बार बैठक हुई। यह समूह अंतरिक्ष एजेंसियों इसरो और नासा का एक सहयोग है । CSJWG ने 2024 में NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसमें पानी, जंगल और कृषि जैसे संसाधनों की निगरानी के लिए दो अलग-अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करके पृथ्वी का मानचित्रण करने की उम्मीद है। [257]

जनवरी 2023 में, भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) पर यूएस-इंडिया इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की। iCET के तहत, दोनों पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। [258]

भारत ने 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए , जिसमें चंद्रमा, मंगल और उससे आगे की खोज पर काम करने वाले 26 अन्य देश शामिल हो गए। और नासा 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू करने के लक्ष्य के साथ इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। [215]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी

सितंबर 2014 में ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीनवंबर 2022 में युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास के उद्घाटन समारोह के दौरान अमेरिकी और भारतीय सेना के सैनिक

2017 डोकलाम गतिरोध और 2020-2021 चीन-भारत झड़प दोनों में , संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को अपने पास मौजूद खुफिया जानकारी प्रदान की, और दोनों पक्षों ने लद्दाख सीमा पर संकट पर चर्चा की। 2019 बालाकोट हवाई हमले के बाद भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तानी हिरासत से छुड़ाने में अमेरिका भी शामिल था । [267] पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के दावे के अनुसार, अमेरिका ने 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करने में भूमिका निभाई, जब पाकिस्तान और भारत परमाणु युद्ध के कगार पर थे । [268]

27 अक्टूबर, 2020 को अमेरिका और भारत ने संवेदनशील उपग्रह डेटा साझा करने पर एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, या बीईसीए, अमेरिका के रणनीतिक साझेदारों को संवेदनशील भू-स्थानिक और वैमानिकी डेटा की एक श्रृंखला तक पहुंचने की अनुमति देता है जो सैन्य कार्यों के लिए उपयोगी है। [269]

दिसंबर 2020 में, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच संबंध 2021 में जारी रहेंगे और मजबूत होंगे, क्योंकि बिडेन प्रशासन समृद्ध आर्थिक संबंधों के लिए अपने व्यापार सौदों को प्राथमिकता देगा। [270]

दिसंबर 2022 में, BECA के आधार पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश में टकराव के दौरान भारत को चीन को हराने में मदद करने के लिए PLA सैनिकों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की । [271]

रूसी संबंधों पर तनाव

भारत द्वारा S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद पर अमेरिकी कांग्रेस में विवाद हो गया । [272] इससे पहले, ट्रम्प प्रशासन ने भारत को चेतावनी दी थी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों का प्रलोभन दे सकता है। [273] [274] लेकिन चूंकि भारत चीन के प्रतिकार के रूप में उभर रहा है , इसलिए अमेरिकी सीनेट में भारत का महत्व बढ़ रहा है । इसके बाद, रिपब्लिकन पार्टी के दो प्रमुख सीनेटर जॉन कॉर्निन और डेमोक्रेटिक पार्टी के मार्क वार्नर ने राष्ट्रपति जो बिडेन से छूट देने का आग्रह किया । नई दिल्ली के खिलाफ प्रतिबंध , क्योंकि यह दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए भारत के साथ संचयी सहयोग को ख़त्म कर सकता है। [275] [276]

2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद , भारत ने आक्रमण के प्रति अस्वीकृति (लेकिन राजनीतिक रूप से निंदा नहीं) दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर रोक लगा दी और कहा कि वह रूस के आक्रमण से "गहराई से परेशान" था। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि भारत के परहेज का कारण यह है कि भारतीय हथियारों का 70% आयात रूस से, 14% अमेरिका से और 5% इज़राइल से होता है । [277] क्षेत्र के लिए संकट के निहितार्थ पर चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता की बैठक में , राष्ट्रपति बिडेन ने भारत की अनुपस्थिति पर ध्यान देते हुए कहा कि अधिकांश वैश्विक सहयोगी रूस के खिलाफ एकजुट थे। [278] अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति से बात करते हुए, अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा कि बिडेन प्रशासन अभी भी रूस के साथ एस -400 सौदे और संयुक्त राष्ट्र में इसकी अनुपस्थिति पर भारत के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। [279] 15 जुलाई 2022 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने एक विधायी संशोधन पारित किया जिसने भारत को एस-400 की खरीद से जुड़े सीएएटीएसए-संबंधित प्रतिबंधों से छूट दी; हालाँकि संशोधन को अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा पारित किया जाना बाकी है । [280]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

जबकि यूक्रेन के कुछ अधिकारियों ने रूसी तेल की भारी खरीद पर भारत के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का आह्वान किया है, यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के अमेरिकी सहायक सचिव करेन डोनफ्राइड ने फरवरी 2023 में संवाददाताओं से कहा: "हम भारत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारी साझेदारी के साथ भारत हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है।" [281] रूस-यूक्रेनी युद्ध के मद्देनजर , अमेरिका ने रूस से पर्याप्त तेल आयात या रक्षा भागीदारी के लिए भारत के खिलाफ माध्यमिक प्रतिबंधों से इनकार कर दिया है। [189]

राजनयिक आदान-प्रदान

समकक्षों द्वारा औपचारिक यात्राएँ (2014 से आगे)

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2014

2014 के भारतीय आम चुनाव के दौरान, भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों के भविष्य के बारे में व्यापक संदेह था। नरेंद्र मोदी, जिनका अमेरिकी वीज़ा गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रद्द कर दिया गया था , 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगभग एक दशक तक [282] उनका बहिष्कार किया गया था । [283] हालांकि, चुनाव से पहले ही मोदी की अपरिहार्य जीत को भांपते हुए अमेरिकी राजदूत नैंसी पॉवेल ने उनसे संपर्क किया था। इसके अलावा, 2014 में भारत के प्रधान मंत्री के रूप में उनके चुनाव के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें टेलीफोन पर बधाई दी और उन्हें अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया। [284] [285] प्रधान मंत्री के रूप में मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा के लिए जमीन तैयार करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने 1 अगस्त को नई दिल्ली का दौरा किया। सितंबर 2014 में, अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले सीएनएन के फरीद जकारिया को दिए एक साक्षात्कार में, मोदी ने कहा था कि "भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास और संस्कृति से एक साथ बंधे हुए हैं" लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि संबंधों में "उतार-चढ़ाव" रहे हैं। . [286] मोदी ने 27 से 30 सितंबर 2014 तक अमेरिका की यात्रा की, [287] शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन से की और उसके बाद न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय अमेरिकी समुदाय द्वारा एक भव्य सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लिया।ओबामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए वाशिंगटन, डीसी जाने से पहले। वहां रहते हुए, मोदी ने कई अमेरिकी व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। [288] [289] [290]

ओबामा की भारत यात्रा, 2015

राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को आयोजित भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। [291] भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मुद्दों पर अपनी पहली द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की। "दिल्ली मैत्री घोषणापत्र" जो 2015 के बाद के विकास एजेंडे के हिस्से के रूप में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत और विस्तारित करता है। [292] प्रमुख घोषणाओं की स्पष्ट अनुपस्थिति, जो मेजबान देश के साथ अमेरिकी संबंधों की स्थिति का एक प्रमुख संकेतक है, ने दोनों देशों के राजनीतिक टिप्पणीकारों को यात्रा के विश्वास-निर्माण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित किया। [293] [294] [295]

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2015

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलिकॉन वैली का दौरा किया और एनडीए सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए सफल माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल संचार और जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप में शामिल उद्यमियों से मुलाकात की - जिनमें से कई भारतीय मूल के व्यक्ति हैं । [296] मोदी ने अमेरिका के पश्चिमी तट को छोड़ दिया और 2015 की संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा की, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2016

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच लोकतंत्र और दीर्घकालिक मित्रता के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डाला। [297] 45 मिनट से अधिक समय के भाषण में, श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच समानताएं बताईं और विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया, जहां दोनों देशों ने अतीत में एक साथ काम किया है और जहां भविष्य की कार्रवाई होगी। [298]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

निष्कर्ष

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2017

26 जून, 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की । 8 नवंबर 2017 को, अमेरिका ने भारत और श्रीलंका में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विचारों और परियोजनाओं के साथ आने वाले संगठनों के लिए लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की । [उद्धरण वांछित]

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2019

सितंबर 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन का दौरा किया , जहां उन्होंने एनआरजी स्टेडियम में एक बड़े भारतीय अमेरिकी दल को संबोधित किया । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ , उन्होंने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की शुरुआत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए भारतीय अमेरिकी संबंधों की फिर से पुष्टि की। [299]

ट्रम्प की 2020 की भारत यात्रा

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में अहमदाबाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को महात्मा गांधी के तीन बुद्धिमान बंदरों का नमूना उपहार में दिया।

फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प रैली में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी

24 फरवरी, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ी भारतीय भीड़ को संबोधित करने के लिए अहमदाबाद , गुजरात का दौरा किया । [300] "नमस्ते ट्रम्प" शीर्षक वाला कार्यक्रम, 2019 में आयोजित "हाउडी मोदी" कार्यक्रम की प्रतिक्रिया थी। [301] 100,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। [302] इस कार्यक्रम ने अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधान मंत्री के लिए अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को दिखाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। [303]

उसी दिन ट्रंप ने आगरा, उत्तर प्रदेश और ताज महल का भी दौरा किया । [304] आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति और प्रथम महिला का स्वागत किया। वहाँ 3000 सांस्कृतिक कलाकार विभिन्न क्षेत्रों की कला, सांस्कृतिक और संगीत का प्रदर्शन कर रहे थे। [305] हालांकि, राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि ट्रम्प की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से प्रभावित हुई थी । [306]

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2021

मोदी ने 22 से 25 सितंबर 2021 तक अमेरिका की यात्रा की, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन से हुई और फिर राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए वाशिंगटन, डीसी गए । वहीं, मोदी ने क्वाड लीडर्स समिट में भी हिस्सा लिया ।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

मोदी की अमेरिका यात्रा, 2023

प्रधान मंत्री मोदी ने जून 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। [307] यह मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा थी , और दूसरी बार उन्हें अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है । [308] मोदी और राष्ट्रपति बिडेन ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। [309]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "चीन प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित, अमेरिका, भारत ने रणनीतिक संबंधों को गहरा किया" । यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस । 21 मई 2023 को पुनःप्राप्त .
2. ^ कोहेन, स्टीफन पी. (जनवरी 2010)। महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष - पाकिस्तान और शीत युद्ध (पीडीएफ) । ब्रुकिंग्स. पीपी. 76, 77, 78. आईएसबीएन 978-0-415-55025-3.
3. ^ "गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) | परिभाषा, मिशन, और तथ्य | ब्रिटानिका" । www.britannica.com । 12 मई, 2023 । 21 मई 2023 को पुनःप्राप्त .
4. ^ ग्रेरे, फ्रेडरिक (27 जुलाई, 2019)। "भारत-अमेरिका संबंधों के तीन दशकों को देखते हुए" ।
5. ^ "भारत के दूतावास, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में आपका स्वागत है" । 26 मार्च 2016 को मूल से संग्रहीत । 2 अप्रैल 2016 को लिया गया .
6. ^ "भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत" (पीडीएफ) । dpcc.co.in . 4 मई 2012 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 25 मार्च, 2018 को लिया गया ।
7. ^ "मोदी सरकार का एक साल: हम बनाम वो" । इंडियन एक्सप्रेस . 25 मई 2015.
8. ^ "ओबामा-मोदी वार्ता के बाद भारत-अमेरिका संयुक्त बयान" । द हिंदू । 25 जनवरी 2015.
9. ^ "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर भारत-अमेरिका में खींचतान" । राजनयिक । 11 जून 2015.
10. ^ "भारत, अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए" । राजनयिक । 30 अगस्त 2016 को लिया गया ।
11. ^ "मजबूत रक्षा संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम में, अमेरिका, भारत ने सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए" । जापान टाइम्स । 30 अगस्त 2016 । 30 अगस्त 2016 को लिया गया ।
12. ^ "भारत, अमेरिका ने प्रमुख रक्षा भागीदार समझौते को अंतिम रूप दिया" । इंडियन एक्सप्रेस । 9 दिसंबर 2016 । 9 दिसंबर 2016 को लिया गया ।
13. ^ माइकल, कुगेलमैन (14 जुलाई, 2022)। "एक और क्वाड का उदय" । विदेश नीति।
14. ^ "कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन अमेरिकियों के सबसे पसंदीदा राष्ट्र हैं" । गैलप.कॉम. 13 मार्च 2015.
15. ^ "कनाडा, ब्रिटेन को अमेरिका में सबसे अधिक पसंद किया गया; रूस, उत्तर कोरिया को सबसे कम" । गैलप डॉट कॉम । गैलप इंक. मार्च 21, 2023 । 25 मार्च 2023 को पुनःप्राप्त .
16. ^ "उत्तर कोरिया अमेरिकियों के बीच सबसे कम लोकप्रिय देश बना हुआ है" । गैलप.कॉम. 20 फरवरी 2017 । पुनः प्राप्त किया 6 फरवरी, 2018 .
17. ^ "अमेरिकियों के चीन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण से 12-पॉइंट हिट" । गैलप डॉट कॉम । 11 मार्च 2019 । 8 सितंबर, 2019 को लिया गया ।
18. ^ "ईरान, उत्तर कोरिया को अमेरिकियों ने सबसे कम पसंद किया" । गैलप डॉट कॉम । इंक गैलप. 3 मार्च 2020 । 21 फरवरी, 2021 को लिया गया ।
19. ^ "अमेरिकियों ने कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान को सबसे अनुकूल दर दी" । गैलप डॉट कॉम । इंक गैलप. 14 मार्च 2022 । 20 अप्रैल, 2022 को लिया गया ।
20. ^ "अफगानिस्तान से अराजक वापसी के बीच दुनिया अमेरिका को कैसे देखती है" । 26 अगस्त 2021.
21. ^ ग्रांट, आरजी (24 अक्टूबर, 2017)। 1001 लड़ाइयाँ जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी । पुस्तक बिक्री, 2017. आईएसबीएन 978-0785835530.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

22. ^ऊपर जायें:[ए बी] स्मिथ, जॉन एल. जूनियर (8 जुलाई, 2015)। "भारत: अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की अंतिम लड़ाई"। अमेरिकी क्रांति का जर्नल। 26 जून, 2023को लिया गया।
23. ^ बोसवेल, जेम्स (1783)। ईस्ट इंडीज़ में मामले ऐप 1783 - उप-प्रशासक के एक पत्र का उद्धरण। सर एडवर्ड ह्यूजेस से लेकर मिस्टर स्टीफंस तक । स्कॉट्स पत्रिका । पीपी. 685-688.
24. ^ फॉसेट, सर चार्ल्स (1937)। "ईस्ट इंडिया कंपनी का धारीदार झंडा, और अमेरिकी 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' के साथ इसका संबंध"। मेरिनर मिरर । 23 (4): 449-476। doi : 10.1080/00253359.1937.10657258 ।(सदस्यता आवश्यक)
25. ^ यूजीन वैन सिकल। "द कांग्रेव रॉकेट्स इन द वॉर ऑफ़ 1812" (पीडीएफ) । डाल्टन स्टेट कॉलेज । मूल (पीडीएफ) से 25 दिसंबर 2014 को संग्रहीत । 9 दिसंबर 2014 को लिया गया .
26. ^ होल्डन फ़र्बर, "भारत-अमेरिकी संबंधों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू," जर्नल ऑफ़ द यूनिवर्सिटी ऑफ़ बॉम्बे (1965), वॉल्यूम। 34 अंक 67/68, पृष्ठ 95-116।
27. ^ श्मिट, बारबरा. "ज्ञात मार्क ट्वेन भाषणों, सार्वजनिक वाचनों और व्याख्यानों का कालक्रम" । marktwainquotes.com । 1 जनवरी 2013 को पुनःप्राप्त .
28. ^ गुप्ता, विपिन; सरन, पंकज (2007)। लेनिनसन, डेविड; क्रिस्टेंसेन, करेन (संस्करण)। संयुक्त राज्य अमेरिका पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य: राष्ट्र द्वारा राष्ट्र सर्वेक्षण । वॉल्यूम. 1. ग्रेट बैरिंगटन, एमए: बर्कशायर पब्लिशिंग ग्रुप। पीपी 294-300 । आईएसबीएन 978-1-933782-06-5.
29. ^ आइजैक, स्क्रैचेज़ ऑन अवर माइंड्स: अमेरिकन व्यूज़ ऑफ़ चाइना एंड इंडिया (1980) पृष्ठ 241
30. ^ विश्वविद्यालय, © स्टैनफोर्ड; स्टैनफोर्ड; कैलिफोर्निया 94305 (25 अप्रैल, 2017)। "गांधी, मोहनदास के।" मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, अनुसंधान और शिक्षा संस्थान । 26 जून, 2023 को लिया गया ।
31. ^ फोस्टर रिया डलेस, और गेराल्ड ई. रिडिंगर। "फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट की उपनिवेशवाद विरोधी नीतियां।" राजनीति विज्ञान त्रैमासिक (1955): 1-18। जेएसटीओआर में
32. ^ केंटन जे. क्लाइमर, क्रेस्ट फॉर फ्रीडम: द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडियाज़ इंडिपेंडेंस (2013)।
33. ^ गोंजालेस, जुआन एल. जूनियर (1986)। "एशियाई भारतीय आप्रवासन पैटर्न: कैलिफोर्निया में सिख समुदाय की उत्पत्ति"। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा । 20 (1): 40-54. डीओआई : 10.1177/019791838602000103 । जेएसटीओआर 2545683 । एस2सीआईडी 145124856 ।
34. ^ रुबिन, एरिक एस. (2011)। "अमेरिका, ब्रिटेन और स्वराज: एंग्लो-अमेरिकी संबंध और भारतीय स्वतंत्रता, 1939-1945"। भारत समीक्षा । 10 (1): 40-80. डीओआई : 10.1080/14736489.2011.548245 । एस2सीआईडी 154301992 ।
35. ^ हरमन, आर्थर (2008)। गांधी और चर्चिल: महाकाव्य प्रतिद्वंद्विता जिसने एक साम्राज्य को नष्ट कर दिया और हमारे युग को गढ़ा । रैंडम हाउस डिजिटल, इंक. पीपी. 472-539। आईएसबीएन 978-0-553-80463-8.
36. ^ इस लेख में वायु सेना ऐतिहासिक अनुसंधान एजेंसी से सार्वजनिक डोमेन सामग्री शामिल है ।
37. ^ मौरर, मौरर (1983)। विश्व युद्ध 2 की वायु सेना की युद्ध इकाइयां। मैक्सवेल एएफबी, अलबामा: वायु सेना इतिहास कार्यालय। आईएसबीएन 0-89201-092-4 .
38. ^ मैकमोहन, रॉबर्ट जे. (1 जून, 2010)। परिधि पर शीत युद्ध: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पाकिस्तान । कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस. पी। 11. आईएसबीएन 978-0-231-51467-5. पाकिस्तान के संभावित रणनीतिक महत्व पर गहन ध्यान देने के बावजूद, अधिकांश अमेरिकी योजनाकारों ने भारत को अधिक मूल्यवान राजनयिक पुरस्कार के रूप में दर्जा दिया। फलस्वरूप 1940 के दशक के अंत में उपमहाद्वीप के प्रति अमेरिकी नीति भारत के पक्ष में झुक गयी। नई दिल्ली और कराची के साथ द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत और प्रारंभिक ट्रूमैन प्रशासन के पूर्व की ओर झुकाव के कारणों का अगले अध्याय में पता लगाया जाएगा।
39. ^ मैकमोहन, रॉबर्ट जे. (13 अगस्त 2013)। परिधि पर शीत युद्ध: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पाकिस्तान । कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस. पी। 40. आईएसबीएन 9780231514675. 28 नवंबर 2015 को लिया गया .
40. ^ सेंट जॉन, एंथोनी वानिस (1997)। "भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद में मध्यस्थता की भूमिका" । विश्व मामलों का फ्लेचर फोरम । 21 (1): 173-195. आईएसएसएन 1046-1868 । जेएसटीओआर 45288985 ।
41. ^ एचडब्ल्यू ब्रांड्स, इनसाइड द कोल्ड वॉर (1991) पृष्ठ 202-05, उद्धरण पृष्ठ 204

42. ^ सर्वपल्ली गोपाल, जवाहरलाल नेहरू: एक जीवनी। 1947-1956. खंड दो (1979) 2:59।
43. ^ गोपाल, नेहरू 2:60.
44. ^ रुद्र चौधरी, फोर्ज्ड इन क्राइसिस: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1947 (2014) पीपी 25-47।
45. ^ रामचंद्रन, डी. पी (19 मार्च, 2017)। "युद्ध के डॉक्टर-नायक" । द हिंदू - www.thehindu.com के माध्यम से।
46. ^ ब्रांड्स, इनसाइड द कोल्ड वॉर (1991) पीपी 212-24, 229
47. ^ रिचर्ड पी. स्टेबिन्स, द यूनाइटेड स्टेट्स इन वर्ल्ड अफेयर्स: 1959 (1960) पृष्ठ 297
48. ^ रिचर्ड पी. स्टेबिन्स, द यूनाइटेड स्टेट्स इन वर्ल्ड अफेयर्स: 1961 (1962) पृष्ठ 208
49. ^ फ्रैंकलिन, डगलस ए. (1984)। "राजनीतिज्ञ के रूप में राजनयिक: भारत में केंटुकी के जॉन शर्मन कूपर, 1955-1956" । केंटकी हिस्टोरिकल सोसायटी का रजिस्टर । 82 (1): 28-59. आईएसएसएन 0023-0243 . जेएसटीओआर 23381056 - जेएसटीओआर के माध्यम से ।
50. ^ सारा एलेन ग्राहम, "द आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक डिप्लोमेसी इन इंडिया: एन एम्बिवेलेंट एंगेजमेंट, 1953-1960।" कूटनीति और शासनकला 25.2 (2014): 260-284।
51. ^ "रणनीतिक काउंटर परमाणु ईंधन आपूर्ति यात्रा" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 21 जनवरी 2009। मूल से 12 मई 2013 को संग्रहीत । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
52. ^ पैडॉक, कार्ल (2009)। भारत-अमेरिका परमाणु समझौता: संभावनाएँ और निहितार्थ । एपिटोम पुस्तकें। आईएसबीएन 978-93-80297-00-2.
53. ^ "अमेरिकी कांग्रेस में भारत की बदलती धारणाएँ" । Sga.myweb.uga.edu. 10 दिसंबर 2009 को मूल से संग्रहीत । 9 नवंबर 2009 को पुनःप्राप्त .
54. ^ सिंघल, डीपी (1962)। "गोवा-एक युग का अंत" । ऑस्ट्रेलियाई त्रैमासिक । 34 (1): 77-89. डीओआई : 10.2307/20633766 । आईएसएसएन 0005-0091 . जेएसटीओआर 20633766 ।
55. ^ "भारत-चीन युद्ध में चीनी घुसपैठ का पता लगाने के लिए भारत ने अमेरिकी जासूसी विमानों का इस्तेमाल किया" । हिंदुस्तान टाइम्स । 16 अगस्त 2013। मूल से 16 अगस्त 2013 को संग्रहीत । 16 अगस्त 2013 को पुनःप्राप्त .
56. ^ "नेहरू ने सीआईए के जासूसी विमानों को भारतीय हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति दी" । बिजनेस स्टैंडर्ड । 16 अगस्त 2013 । 16 अगस्त 2013 को पुनःप्राप्त .
57. ^ "द अनटोल्ड स्टोरी- कैसे अमेरिका भारत की सहायता के लिए आया" । Rediff.com । 4 दिसंबर 2012 । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
58. ^ सुकुमारन, आर. (जुलाई-सितंबर 2003)। "1962 का भारत-चीन युद्ध और कारगिल 1999: वायु शक्ति के उपयोग पर प्रतिबंध" (पीडीएफ) । रणनीतिक विश्लेषण . 27 (3): 332-356। डीओआई : 10.1080/09700160308450094 । एस2सीआईडी 154278010 । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
59. ^ "जेएफके, सहयोगियों ने चीन-भारत संघर्ष में परमाणु हथियार माना" । 27 अगस्त 2005 । 27 सितम्बर 2014 को पुनःप्राप्त .
60. ^ "IACFPA.ORG में आपका स्वागत है" । 27 सितम्बर 2007 को मूल से संग्रहीत । 27 सितम्बर 2014 को पुनःप्राप्त .
61. ^ मदन, तन्वी (17 मई, 2013)। "व्यक्तित्व अपनी जगह पर" । इंडियन एक्सप्रेस । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
62. ^ "लिंडन जॉनसन और भारत" । फ्रंटलाइन.इन. 11 मई 2001 . 30 दिसंबर 2015 को लिया गया .
63. ^ "विदेशी संबंध, 1969-1976, खंड ई-7, दक्षिण एशिया पर दस्तावेज़, 1969-1972" । अमेरिकी विदेश विभाग . 20 अक्टूबर 2009 को पुनःप्राप्त .
64. ^ "निक्सन की 'चुड़ैल' इंदिरा के प्रति नापसंदगी" । बीबीसी समाचार । 29 जून 2005 । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
65. ^ "द टिल्ट: द यूएस एंड द साउथ एशियन क्राइसिस ऑफ़ 1971" । nsarchive2.gwu.edu । 25 जून, 2023 को लिया गया ।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

66. ^ पेरकोविच, जॉर्ज (2002)। भारत का परमाणु बम: वैश्विक प्रसार पर प्रभाव । कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस. आईएसबीएन 978-0-520-23210-5.
67. ^ "परमाणु तालाब में लहरें" । द डेसेरेट न्यूज़ । 22 मई 1974 . 5 सितम्बर 2011 को पुनःप्राप्त .
68. ^ "कार्यकारी आदेश 12055 - भारत को विशेष परमाणु सामग्री का निर्यात" । अमेरिकी प्रेसीडेंसी परियोजना । Ucsb.edu. 17 दिसंबर 2013 को मूल से संग्रहीत । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
69. ^ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप और डिटेंटे का पतन
70. ^ ब्रूस्टर, डेविड. भारत का महासागर: क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए भारत की कोशिश की कहानी। 30 अगस्त 2014 को लिया गया .
71. ^ रुबिनॉफ, आर्थर जी. (1996)। "छूटे हुए अवसर और विरोधाभासी नीतियां: क्लिंटन-राव वर्षों में भारत-अमेरिकी संबंध" । प्रशांत मामले . 69 (4): 499-517. डीओआई : 10.2307/2761184 । आईएसएसएन 0030-851X . जेएसटीओआर 2761184 ।
72. ^ स्ट्रोब टैलबोट (2004)। संलग्न भारत । इंटरनेट पुरालेख. ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस। आईएसबीएन 978-0-8157-8300-8.
73. ^ "क्लिंटन ने भारत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया" । बिजनेस स्टैंडर्ड । 14 मई 1998 । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
74. ^ऊपर जायें:[ए बी] हैथवे, रॉबर्ट (2002)। "अमेरिका-भारत प्रेमालाप: क्लिंटन से बुश तक"। सामरिक अध्ययन जर्नल। 25(4): 6-31. डीओआई:10.1080/01402390412331302855। आईएसएसएन0140-2390. एस2सीआईडी153681638।
75. ^ कुके, बिलाल (24 फरवरी, 2020)। "अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा की समयरेखा" । अल जज़ीरा । 12 अप्रैल, 2023 को लिया गया ।
76. ^ न्यूराइटर, नॉर्मन; चीथम, माइकल (16 दिसंबर, 2013)। "द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच" । विज्ञान और कूटनीति . 2 (4).
77. ^ लिमये, सातु पी. "अमेरिका-भारत संबंध: नग्न आंखों को दिखाई देने योग्य" (पीडीएफ) । सुरक्षा अध्ययन के लिए एशिया-प्रशांत केंद्र। मूल (पीडीएफ) से 18 मई 2013 को संग्रहीत । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
78. ^ "अमेरिका भारत को गैर-नाटो सहयोगी मानता है" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 23 मार्च 2004 । 2 अप्रैल 2016 को लिया गया .
79. ^ "अमेरिका-भारत रणनीतिक टैंगो में, यह जुनून बनाम सावधानी है" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 13 जून 2012 । 2 अप्रैल 2016 को लिया गया .
80. ^ इजाज़, अहमद. "संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत संबंध: एक विस्तारित रणनीतिक साझेदारी" (पीडीएफ) । पाकिस्तान विज़न . 13 (1) . 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
81. ^ "दुनिया को भारत की जरूरत है: बुश" । www.rediff.com । 3 मार्च 2006.
82. ^ ज़कारिया, फ़रीद, द पोस्ट-अमेरिकन वर्ल्ड, 2008 कैप्टर VII, पीपी. 225-226
83. ^ लस्कर, रेजौल (दिसंबर 2013)। "कूटनीति के माध्यम से राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना"। असाधारण और पूर्णाधिकारी कूटनीतिज्ञ । 1 (9): 60.
84. ^ "भारतीय नौसेना कूटनीति: सुनामी के बाद | आईपीसीएस" । www.ipcs.org . 24 अप्रैल, 2021 को लिया गया ।
85. ^ "भारत में बोइंग के बारे में" । बोइंग इंडिया. 9 फ़रवरी 2014 को मूल से संग्रहीत । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
86. ^ डोलन, ब्रिजेट एम. (दिसंबर 10, 2012)। "विज्ञान कूटनीति के लिए उपकरण के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते" । विज्ञान और कूटनीति . 1 (4).
87. ^ "भारत ने कैटरीना को राहत के लिए 5 मिलियन डॉलर देने का वादा किया" । la.rediff.com. 3 सितम्बर 2005 . 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
88. ^ऊपर जायें:[ए बी] "भारत बुला रहा है! जॉर्ज बुश 2006 में आएंगे"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 23 दिसंबर 2005।आईएसएसएन0971-8257। 25 जून, 2023को लिया गया।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

89. ^ "अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश" । संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
90. ^ "बुश प्रशासन में भारतीय अमेरिकियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 7 फ़रवरी 2004। आईएसएसएन 0971-8257 । 26 जून, 2023 को लिया गया ।
91. ^ "वाणिज्य व्यापार अधिकारी भारत में शिक्षा व्यापार मिशन का नेतृत्व करेंगे" । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन। 6 अक्टूबर, 2011. 17 अक्टूबर 2012 को मूल से संग्रहीत । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
92. ^ "ओबामा ने आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार पर भारत का समर्थन किया" । द हिंदू । 8 नवंबर 2010। आईएसएसएन 0971-751एक्स । 25 जून, 2023 को लिया गया ।
93. ^ "ओबामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन करते हैं" । स्वतंत्र . लंडन। एपी. 8 नवंबर 2010 । 17 दिसंबर 2013 को लिया गया .
94. ^ "यूएस ओके ने भारत को 2.1 अरब डॉलर की हथियार बिक्री का रिकॉर्ड बनाया" । रॉयटर्स. 16 मार्च 2009 । 2 अप्रैल 2016 को लिया गया .
95. ^ कोहेन, स्टीफन और सानिल दासगुप्ता। "भारत के लिए हथियारों की बिक्री" । ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन। 9 मार्च 2011 को मूल से संग्रहीत । 18 मार्च 2011 को पुनःप्राप्त .
96. ^ "बोइंग एक और भारतीय हेलीकॉप्टर अनुबंध जीत सकता है" । 20 नवंबर 2012. 22 जनवरी 2013 को मूल से संग्रहीत।
97. ^ "पेंटागन रिपोर्ट: भारतीय नौसेना का नया पनडुब्बी शिकारी अप्रभावी है" । 25 जनवरी 2014.
98. ^ "नेवल एयर: द बोइंग पी-8 स्टंबल्स" । 5 फ़रवरी 2014.
99. ^ "भारत अमेरिका के लिए एक रणनीतिक भागीदार के रूप में उभरा है: मुलेन" । द हिंदू । 25 मार्च, 2018 को लिया गया ।
100. ^ "भारत, अमेरिका ने रणनीतिक वार्ता शुरू की - वैश्विक सुरक्षा न्यूज़वायर - एनटीआई" । एनटीआई: परमाणु खतरा पहल । 5 नवंबर 2010 को मूल से संग्रहीत । 27 सितम्बर 2014 को पुनःप्राप्त .
101. ^ "अमेरिका-भारत संबंध का दायरा वैश्विक है: पेंटागन" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 2 अगस्त 2012.
102. ^ "भारत अपनी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी पर एनएसए द्वारा जासूसी करने की रिपोर्ट से पीछे हट गया है" । ईसाई विज्ञान मॉनिटर । 3 जुलाई 2014.
103. ^ "भारत ने जासूसी के दावों पर अमेरिकी राजनयिकों को बुलाया" । वॉल स्ट्रीट जर्नल । 2 जुलाई 2014.
104. ^ "अमेरिका को उम्मीद है कि एनएसए की भाजपा पर जासूसी से द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा" । इंडिया टुडे । 2 जुलाई 2014.
105. ^ "जासूसी रिपोर्ट पर भारत अमेरिका से आश्वासन चाहता है" । रॉयटर्स इंडिया. 3 जुलाई 2014.
106. ^ "मोदी पार्टी की जासूसी के बाद भारत ने अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगा" । ब्लूमबर्ग. 3 जुलाई 2014.
107. ^ "नरेंद्र मोदी सरकार ने एनजीओ पर नकेल कसी, हिटलिस्ट तैयार की" । हिंदुस्तान टाइम्स । 24 जनवरी 2014। मूल से 24 जनवरी 2015 को संग्रहीत ।
108. ^ "The foreign threat". The Indian Express. May 15, 2015.
109. ^ "No call from Obama seen as slight to India". Retrieved September 27, 2014.
110. ^ "Narayanan has barked up the wrong tree now". The Times Of India. February 5, 2009.
111. ^ "India needs a lot more love from Obama". Foreign Policy. February 20, 2009. Retrieved March 25, 2018.
112. ^ "India's Terror Stance Vexes Obama Amid Voter Ire at Pakistan". Bloomberg.com. Archived from the original on July 21, 2012. Retrieved March 25, 2018.
113. ^ "We're sorry, that page can't be found". state.gov. Archived from the original on July 5, 2009. Retrieved March 25, 2018.
114. ^ "We're sorry, that page can't be found". state.gov. Archived from the original on July 15, 2009. Retrieved March 25, 2018.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

115. ^ "India says it will oppose U.S. 'protectionism'". Retrieved April 2, 2016.
116. ^ "India may contest Obama's move against outsourcing in WTO". Archived from the original on May 1, 2009.
117. ^ "Obama on outsourcing is no reason to panic". February 27, 2009. Retrieved April 2, 2016.
118. ^ "U.S.-India Relations Strained under Obama". Archived from the original on July 4, 2009. Retrieved April 2, 2016.
119. ^ "Remarks at U.S.-India Business Council's 34th Anniversary "Synergies Summit"". June 22, 2009. Archived from the original on June 22, 2009.
120. ^ Kronstadt, K. Alan; Kerr, Paul K.; Martin, Michael F.; Vaughn, Bruce (September 1, 2011). India: Domestic Issues, Strategic Dynamics, and U.S. Relations (PDF). Congressional Research Service (Report).
121. ^ "Remarks by the President to the Joint Session of the Indian Parliament in New Delhi, India". whitehouse.gov. November 8, 2010. Retrieved September 27, 2014 – via National Archives.
122. ^ "U.S.-INDIA STRATEGIC DIALOGUE – Consulate General of the United States Hyderabad, India". Archived from the original on February 16, 2013. Retrieved September 27, 2014.
123. ^ "U.S.-India Strategic Dialogue Joint Statement". U.S. Department of State. Retrieved September 27, 2014.
124. ^ "Richard Nixon visited India in 1969 after becoming the president". www.tribuneindia.com.
125. ^ Stolberg, Sheryl (November 8, 2010). "Obama Backs India for Seat on Security Council". The New York Times. Archived from the original on May 11, 2011. Retrieved November 8, 2010.
126. ^ Reynolds, Paul (November 8, 2010). "Obama confirms U.S. strategic shift towards India". BBC. Retrieved November 8, 2010.
127. ^ Jump up to:[a] [b] Harris, Gardiner (December 17, 2013). "Outrage in India, and Retaliation, Over a Female Diplomat's Arrest in New York". The New York Times. Bangalore.
128. ^ Gayathri, Amrutha (December 18, 2013). "Devyani Khobragade: US-India Row Escalates After Diplomat Complains About Strip-Search After Arrest On Visa Fraud". International Business Times. Retrieved September 27, 2014.
129. ^ "Devyani Khobragade row: US refuses to drop charges". BBC News. December 20, 2013.
130. ^ Asokan, Shyamantha; Francescani, Chris (December 18, 2013). "India removes U.S. Embassy security barriers in spat". Reuters. New Delhi/New York. Retrieved December 29, 2013.
131. ^ Daniel, Frank Jack (January 8, 2014). "India bars non-diplomats from US embassy club amid escalating spat". NBC News. Reuters. Archived from the original on January 8, 2014.
132. ^ Dikshit, Sandeep (December 4, 2021) [2014-01-08]. "India asks US Embassy to stop commercial activities". The Hindu. New Delhi.
133. ^ burke, Jason (January 8, 2014). "India cracks down on US embassy club in diplomatic row". The Guardian. Delhi.
134. ^ Harris, Gardiner (December 27, 2013). "India Finds New Methods to Punish U.S. Diplomats". The New York Times. New Delhi.
135. ^ "I-T dept 'discreetly' probing US embassy school". Hindustan Times. New Delhi. February 9, 2014. Archived from the original on February 10, 2014.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

136. ^ Harris, Gardiner; Weiser, Benjamin (January 15, 2014). "American Embassy School in India Ensnared in U.S. Diplomatic Spat". The New York Times. New Delhi.
137. ^ Gowen, Annie (March 13, 2014). "As charges against Devyani Khobragade are dropped, relief and lingering doubts in India". The Washington Post. New Delhi.
138. ^ Jump up to:[a] [b] Barry, Ellen (December 20, 2014). "India Tires of Diplomatic Rift Over Arrest of Devyani Khobragade". The New York Times. New Delhi.
139. ^ Bagchi, Indrani (February 17, 2014). "US refuses to talk China with India". The Times of India.
140. ^ Lakshmi, Rama; DeYoung, Karen (January 8, 2014). "India targets expatriates' privileges at U.S. club amid dispute over diplomat's arrest". The Washington Post. New Delhi.
141. ^ Buncombe, Andrew (December 17, 2013). "India-US row over arrest of diplomat Devyani Khobragade in New York escalates". The Independent. London.
142. ^ "Punish US diplomats with same sex companions: Yashwant Sinha". Press Trust of India. Business Standard. December 19, 2013 [December 17, 2013].
143. ^ "The New Indian Government (Video of Panel Discussion)". Council on Foreign Relations (CFR). May 28, 2014. Archived from the original on May 31, 2014. Retrieved May 30, 2014.
144. ^ Mehta, Manik (May 29, 2014). "US To Warm Up To India After Prime Minister Modi's Win". Bernama. New York. Archived from the original on May 31, 2014. Retrieved May 29, 2014.
145. ^ "U.S. Evangelicals, Indian Expats Teamed Up to Push Through Modi Visa Ban". The New York Times. December 5, 2013.
146. ^ "India Swears In PM as South Asian Leaders Watch". Voice of America (VOA). May 19, 2014.
147. ^ "Washington clears Modi for visit after ban". The Express Tribune. May 19, 2014.
148. ^ "गुजराती मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वीज़ा आवेदन को अस्वीकार करना और वीज़ा रद्द करना" । यू। एस। स्टेट का विभाग। 18 मार्च 2005.
149. ^ "नरेंद्र मोदी के बारे में चार गलत धारणाएँ" । राजनयिक । 28 मई 2013.
150. ^ "दैनिक प्रेस वार्ता: नरेंद्र मोदी का रद्द किया गया अमेरिकी वीजा" । यू। एस। स्टेट का विभाग। 13 सितंबर 2013.
151. ^ "उत्पादक लेकिन आनंदहीन? नरेंद्र मोदी और अमेरिका-भारत संबंध" । कार्नेगी दक्षिण एशिया कार्यक्रम। 12 मई 2013.
152. ^ "चुनाव के बाद: अमेरिका-भारत संबंधों को पुनर्जीवित करने का अवसर" । हेरिटेज फाउंडेशन. 2 जून 2014.
153. ^ "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2005" । यू। एस। स्टेट का विभाग। 8 नवम्बर 2005। मूल से 19 अगस्त 2014 को संग्रहीत । 3 जून 2014 को पुनःप्राप्त .
154. ^ "नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 27 सितम्बर 2014 को पुनःप्राप्त .
155. ^ "यूएससीआईआरएफ की 2013 की वार्षिक रिपोर्ट" । अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग (USCIRF)। 1 मई, 2013।
156. ^ "भारत और मोदी पर अमेरिकी नीति को बदलने की जरूरत है" । वाशिंगटन पोस्ट । 16 मई 2013.
157. ^ "अमेरिकी पैनल ने नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंध जारी रखने का आह्वान किया, धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत की आलोचना की" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 1 मई, 2013।
158. ^ "पहले वीजा देने से इनकार कर दिया गया था, नए भारतीय प्रधान मंत्री का अमेरिका में 'स्वागत किया जाएगा'" सीएनएन। 16 मई 2013.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

159. ^ राजघट्टा, सी. (18 मई 2014)। "'रीसेट' फोन कॉल में, ओबामा ने मोदी के आसपास के दशकों के कलंक को मिटा दिया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 3 जून 2014 को पुनःप्राप्त .
160. ^ "ओबामा को मोदी से बातचीत करने के लिए स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए: रॉबर्ट ब्लैकविल" । इकोनॉमिक टाइम्स । 11 जून 2014.
161. ^ "भारत के लिए मार्ग" । विदेश संबंधों की परिषद। 1 अक्टूबर 2014.
162. ^ एडवर्ड-आइज़ैक डोवेरे (25 जनवरी, 2015)। "नरेंद्र मोदी पर बराक ओबामा का जोखिम भरा दांव" । राजनीतिक . 2 अप्रैल 2016 को लिया गया .
163. ^ मान, जेम्स (3 मई 2014)। "अमेरिका ने नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंध क्यों लगाया" । वॉल स्ट्रीट जर्नल । 2 अप्रैल 2016 को लिया गया .
164. ^ "मोदी ने भारत-अमेरिका संबंध कैसे बदल दिए" । 10 मई 2016.
165. ^ टेरेसिटा सी. शेफ़र, 21वीं सदी में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका: साझेदारी को फिर से स्थापित करना (2010)
166. ^ "भारत-अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंध" (पीडीएफ) । अमेरिकी वैज्ञानिकों का संघ । 25 मार्च, 2018 को लिया गया ।
167. ^ "भारत-अमेरिका संबंध: पठार से आगे बढ़ना" । विदेश नीति . 30 जुलाई 2015.
168. ^ "तत्काल वर्तमान से परे" । द हिंदू । 26 जनवरी 2015.
169. ^ "निक्सन की 'चुड़ैल' इंदिरा के प्रति नापसंदगी" । बीबीसी वर्ल्ड सर्विस। 29 जून 2005.
170. ^ "भारत ने क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को पार कर लिया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 6 जनवरी 2014.
171. ^ "कैसे कारगिल ने भारत को अपना जीपीएस डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 5 अप्रैल 2014.
172. ^ "भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन कंपोजिट के निर्माण पर पश्चिमी प्रतिबंध को विफल कर दिया" । विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। 30 अगस्त 1992.
173. ^ "भारत-अमेरिका संबंधों का भूराजनीतिक संदर्भ" । जी नेवस। 23 सितंबर 2015.
174. ^ "अमेरिका ने भारत के साथ संधि गठबंधन से इनकार किया, कहा कि युग खत्म हो गया है" । इंडिया टाइम्स । 13 अक्टूबर 2016 । 14 अक्टूबर 2016 को लिया गया ।
175. ^ "यूएसए सर्वश्रेष्ठ: भारतीय अमेरिकी शीर्ष समुदाय - विश्व - आईबीएनलाइव" । Ibnlive.in.com. 20 फ़रवरी 2009. 22 फ़रवरी 2009 को मूल से संग्रहीत । पुनः प्राप्त किया 7 फरवरी, 2013 .
176. ^ "घरेलू आय: 2018 अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षण संक्षिप्त" (पीडीएफ) ।
177. ^ "सरकार ने कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई को उतारे जाने का बचाव किया, पश्चिम की अधिकार रिपोर्टों की आलोचना की" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 16 फ़रवरी 2015.
178. ^ "देवयानी खोबरागड़े को अमेरिकी मानव तस्करी रिपोर्ट में शामिल किया गया" । द हिंदू । 21 जून 2014.
179. ^ "भारत ने मधुर संबंधों के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों के दौरे को रोक दिया" । रॉयटर्स. 20 नवंबर 2015.
180. ^ "अमेरिका पाकिस्तान को आठ एफ-16 देगा, भारत नाराज" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 14 फ़रवरी 2016.
181. ^ "अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री से भारत निराश" । मिलिट्री टाइम्स । 14 फ़रवरी 2016.
182. ^ "अमेरिका को पाकिस्तान को F-16 का परमाणु-सशस्त्र संस्करण नहीं बेचना चाहिए: रिपब्लिकन नेतृत्व" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 18 नवंबर 2015.
183. ^ "पाकिस्तान को F-16 भारत-अमेरिका संबंधों के सार पर सवाल उठाता है: थरूर" । सिफी न्यूज । 14 फरवरी 2016। मूल से 13 फरवरी 2016 को संग्रहीत।
184. ^ "एफ-16, परवेज मुशर्रफ ने भारत-पाक वार्ता पर ठंडा पानी डाला" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 15 फ़रवरी 2016.

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

185. ^ "भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है: शीर्ष अमेरिकी गवर्नर" । धन नियंत्रण . 25 फरवरी 2017 । पुनः प्राप्त किया 25 फरवरी, 2017 .

186. ^ "रूसी हथियार सौदों के लिए प्रतिबंधों का सामना कर रहे भारत का कहना है कि वह खर्च को अमेरिका की ओर मोड़ना चाहता है" । सीएनबीसी । 23 मई 2019.

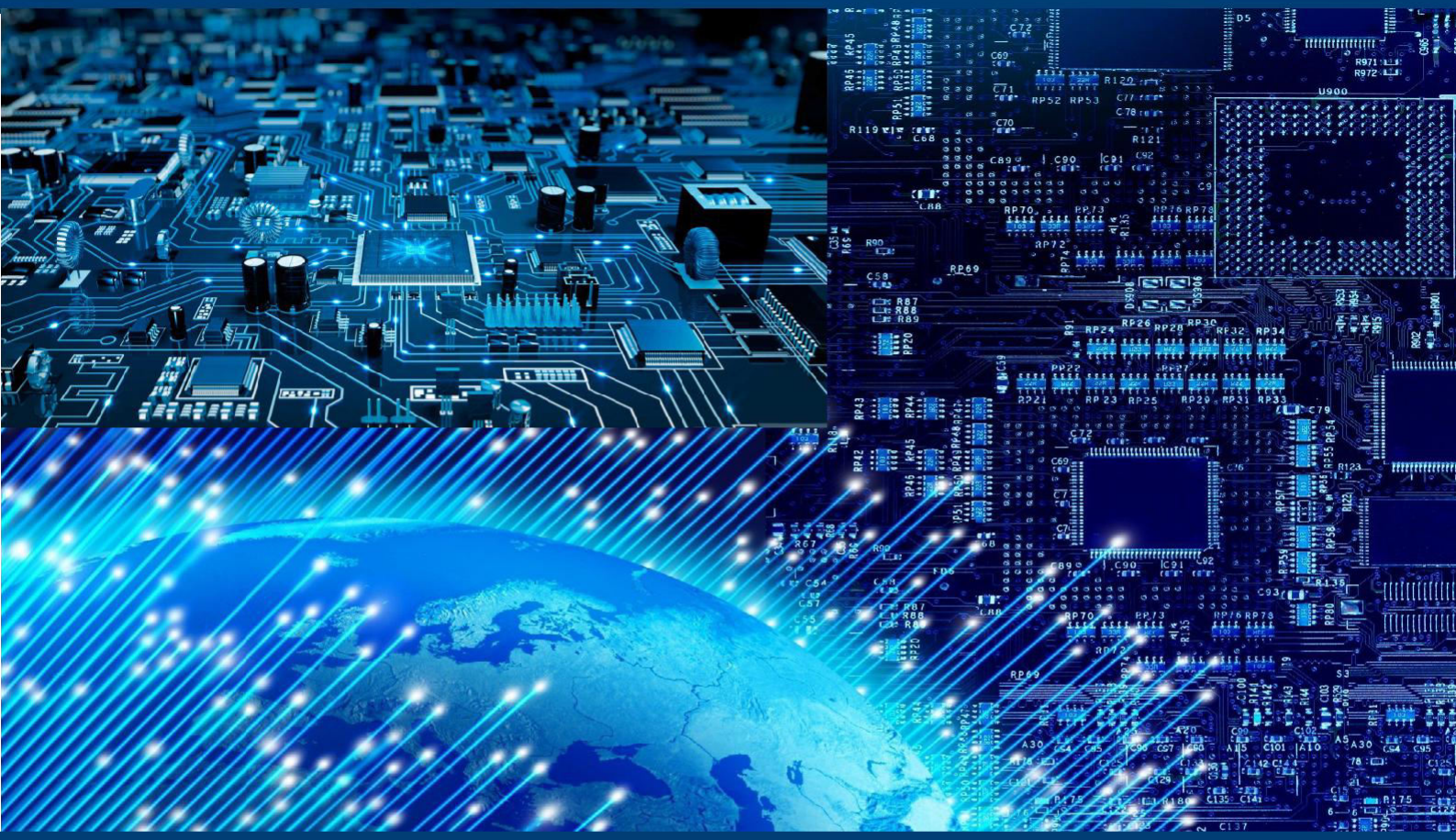

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |